











# विचारमंथन

# दिल्ली में दो सरकारों की लड़ाई

# क्वाड अब प्राथमिकता नहीं

2018 में चीन के साथ शुरू हुए शीत युद्ध के क्रम में संभवतः अमेरिका को क्वाड की जरूरत महसूस हुई, तो इस समूह को खुब महत्व मिला।

2017 ने कानून पर अप्रूद तुरुद तुरुद का लगाया था। जलाली का कोंक्वाड की जरूरत महसूस हुई, तो इस समूह को खबू महत्व मिला। लेकिन अब बनी परिस्थितियों में यह समूह उसके लिए उत्तरा अहम नहीं रह गया है। अमेरिका की इडो-पैसिफिक रणनीति के तहत बनाया गया समूह- ब्वाइंगुलन सिक्युरिटी डॉयलांग (व्हाड) अमेरिका की प्राथमिकता में नीचे चला गया है। इस बात का संकेत तो तभी मिल गया, जब पिछले महीने क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आने से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इनकार कर दिया। इस कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह योजना कामयाब नहीं हो सकी कि क्वाड में शामिल अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेता 25 जनवरी को क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में साझा मुख्य अतिथि होंगे। अब नई दिल्ली स्थित अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटो स्पष्ट किया है कि क्वाड का संचालक की कुर्सी पर भारत विराजमान है और अमेरिका उसकी बगल की सीट पर बैठा है, जिसके पास सिर्फ भटकाव सुधार का हैंडल है। इसका अर्थ यह संदेश है कि क्वाड को क्या भूमिका देनी है, यह भारत खुद तय करे। उन्होंने जो कहा कि उसका अर्थ यह भी है कि फिलहाल क्वाड दिशानिहान है।

मुख्यमंत्री अटारिवंद केजरीवाल का दावा है कि उनको सरकार कुल बजट का 14 फीसदी के करीब हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च करती है, जबकि भारत सरकार का खर्च दो फीसदी के करीब है। दिल्ली सरकार का दावा है कि उसने दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार कर दिया है। दूसरी ओर उप राज्यपाल ने तीन फरवरी को मुख्यमंत्री को पिंग लिख कर गीडिया रिपोर्ट के हवाले दिल्ली के अस्पतालों की दर्यनीय स्थिति के बारे में सचाल पूछे हैं। दिलचस्प बात यह है कि केजरीवाल ने अस्पतालों की दर्यनीय स्थिति के आरोपों को खालिज नहीं किया है, बल्कि कहा है कि दिल्ली के वित व स्वास्थ्य संविधान के कारण ऐसा है। उनका कहना है कि अगर इन दो संविधानों को हटा दिया जाए तो स्थिति सुधार जाएगी। सोरे, क्या सही है? विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा या संविधानों की वजह से अस्पतालों की दर्यनीय दशा? हफ्तीकृत यह है कि दिल्ली के अस्पताल बाजे से बदतर हो गए हैं। केजरीवाल भले जो भी दावा करें लेकिन दिल्ली के लोग भी इलाज के लिए दिल्ली के अस्पतालों का प्राथमिकता नहीं देते हैं। वे केंद्र सरकार के अस्पतालों जैसे एम्स, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया, लेडी हार्डिंग जैसे अस्पतालों में जाना चाहते हैं। दिल्ली के अस्पताल उनकी मजबूरी हैं।



## अजात ध्वंसा- लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

है। राजधानी दिल्ली में दो सरकारें हैं। एक दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार, जो विधानसभा के प्रति जिम्मेदार है और जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं तो दूसरी केंद्रीय सरकार, जो संसद के प्रति जिम्मेदार है और दिल्ली में जिसके मुखिया उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। केंद्र ने एक कानून बनाया है, जिसका नाम जीएनसीटीडी एकट वानी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल टेरेटरी दिल्ली एकट है और इसके मुताबिक उपराज्यपाल ही सल्ली सरकार हैं। केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी राज्य में विपक्ष में है और राज्य में सत्तारूढ़ दल केंद्र में विपक्ष में है। इससे दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था और भी अनोखी हो गई है। जो सरकार में है वह विपक्ष में भी है और जो विपक्ष में है वह सरकार में भी है। इसलिए दोनों अपने को दिल्ली का मालिक मानते हैं और दिल्ली की सत्ता के लिए लड़ते रहते हैं। दोनों के बारे में एक और अनोखी बात यह है कि दोनों प्रचार की राजनीति

यह है कि दिल्ली में सब कुछ ठप्प पड़ा हुआ है। दोनों पार्टीयों के झगड़े से दिल्ली और समूचे एनसीआर के लोगों को किस तरह की मुश्किलें हैं, इसका एक नमूना दो फरवरी को देखने को मिला, जिस दिन दोनों पार्टीयों ने अलग अलग मुद्दों पर प्रदर्शन किया था। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में जनादेश चुरा लिया। उसने 20 वोट होने के बावजूद आप और कांग्रेस के आठ वोट अवैध कर दिए और अपने 16 वोट के आधार पर मेयर का चुनाव जीत गई। इसे लेकर आप ने दिल्ली में प्रदर्शन किया तो दूसरी ओर भाजपा ने मुख्यमंत्री अरविंद केरिवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और कहा कि वे गिरफतारी के डर से शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईंडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचे थे और आप ने पंजाब, हरियाणा

गर भाजपा ने भी दिल्ली के साथ साथ ए एनसीआर से लोगों को जुटाया इसी तीजा यह हुआ है कि दिल्ली की लल्ली के अंदर कई सड़कें बंद रहीं आमकाजी दिन में पूरे दिन सड़कों पर विधायण जाम लगा रहा और लोग संघर्ष रते रहे। दोनों की लडाई का यह एक टाटा नमूना है। अभी एक नया मामला दिल्ली के अस्पतालों का सामने आया। मुख्यमंत्री अरविंद के जरीवाला दाव है कि उनकी सरकार कुल जट का 14 फीसदी के करीब हिस्से वास्थ्य पर खर्च करती है, जबकि उत्तर सरकार का खर्च दो फीसदी के रिव है। दिल्ली सरकार का दाव है कि उसने दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा सुधार कर दिया है। दूसरी ओर उपराज्यपाल ने तीन फरवरी को अख्यमंत्री को ची लिख कर मीडिया पोर्ट के हवाले दिल्ली के अस्पतालों की दयनीय स्थिति के बारे में सचावाल छेहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि

स्थिति के अरापों को खारिज नहीं किया है, बल्कि कहा है कि दिल्ली के वित्त व स्वास्थ्य सचिवों के कारण ऐसा है। उनका कहना है कि अगर इन दो सचिवों को हटा दिया जाए तो स्थिति सुधार जाएगी। सोचें, क्या सही है? विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा या सचिवों की वजह से अस्पतालों की दयनीय दशा? हकीकत यह है कि दिल्ली के अस्पताल बदबू से बदर हो गए हैं। केजरीवाल भले जो भी दावा करें लेकिन दिल्ली के लोग भी इलाज के लिए दिल्ली के अस्पतालों को प्राथमिकता नहीं देते हैं। वे केंद्र सरकार के अस्पतालों जैसे एम्स, सफररजंग, राम मनोहर लohिया, लेडी हार्डिंग जैसे अस्पतालों में जाना चाहते हैं। दिल्ली के अस्पताल उनकी मजबूरी है। विश्वस्तरीय अस्पताल बनाने के दावे की हकीकत यह है कि ज्यादातर अस्पतालों में मरीजों के जांच की सुविधा नहीं है और आए दिन खबर आ रही है कि मरीज भटकते

जिससे मरीज की जान चली गई। दो जनवरी को दिल्ली पुलिस एक घायल को लेकर भटकती रही थी। दिल्ली के तीन अस्पतालों- जग प्रवेश चंद, जीटीबी और एलएनजेपी में इलाज की बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलीं और आठ घंटे भटकने के बाद घायल को राम मनोहर लोहिया ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। यह एक प्रतिनिधि घटना है। ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं। ऊपर से आरोप है कि दिल्ली सरकार की मुफ्त जांच योजना के तहत भारी घोटाला हुआ है। मोहल्ला क्लीनिक से लेकर दिल्ली सरकार के अस्पतालों में डॉक्टरों की हाजिरी अपने आप बनती रही, फर्जी मरीजों का इलाज चलता रहा और उनकी फर्जी जांच निजी लैब्स में होती रही। सैकड़ों करोड़ रुपए के इस घोटाले की जांच के अदेश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने की फरिश्ते योजना शुरू की थी वह कि उप राज्यपाल ने राशि की मंजूरी रोक रखी है। चाहे दिल्ली सरकार की अकर्मण्यता की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं बिगड़ी हों या सचिवों के कारण और उप राज्यपाल के फंड रोके के कारण कारण बिगड़ी हों लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली के लोगों को विश्वस्तरीय तो छोड़िए सामान्य स्वास्थ्य मुहिवाधा भी नहीं मिल रही है। स्वास्थ्य के अलावा दिल्ली सरकार का दूसरा दावा विश्वस्तरीय शिक्षा व्यवस्था का है। इसकी अलग कहानी है। दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेज ऐसे हैं जिनको फंड दिल्ली सरकार देती है कि शिक्षा के लिए कथित तौर पर प्रतिबद्ध दिल्ली सरकार ने इन कॉलेजों का फंड रोक दिया है। दिल्ली सरकार चाहती है कि उसे इन कॉलेजों के प्रशासन का पूरा अधिकार मिले या इन कॉलेजों को दिल्ली विश्वविद्यालय से निकाल कर राज्य सरकार के विश्वविद्यालय के अधीन कर दिया जाए तो राज्य सरकार फंड देगी।

हटपा हाटपा- जब तो लाभा, वह तो साभा का पता ह  
हां के कलेक्टर के आदेश का तत्कालीन (अब इंदौर) संभागायुक्त माल सिंह भायडिया द्वारा भी  
गत-प्रतिशत पालन के निर्देश दिए गए होते तो फैक्ट्री बंद रहती। ऐसा नहीं हां तो दोषी पशासनिक

अधिकारी भी हैं, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण बिना इतनी ढील देना संभव ही नहीं! मप्र में पटाखों, बारुड़ से विस्फोट की यह पहली घटना नहीं है। मुरैना, राऊ में पटाखा फैट्री में विस्फोट में हुई मौतें, पेटलाव में 7 दर्जन से अधिक निदोषों की थीथड़ों की पोटलियों वाले लोमहर्षक दृश्य और जांच समिति की घोषणा लोग भूले नहीं हैं। इससे पहले बालाघाट में 29 और दमोह 7 लोगों की मौत भी ऐसे ही विस्फोट में हुई चुकी है। इन सारे विस्फोट के बाद अब यदि लोगों को यह लगने लगे कि 18 वर्ष के बाद बस सीएस बदले हैं... लापरवाही का ढर्रा वैसा ही चल रहा है तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए! अब जो होगा, वह भी लोगों को पता है... गुना बस हादसे के बाद जिस तरह बसों की चैकिंग का अभियान चला था, वैसी ही इंदौर, भोपाल, दमोह, बालाघाट, हरदा आदि शहरों में पटाखा निमार्ताओं, दुकानदारों के खिलाफ सख्ती परखवाड़ाइ चलाकर लापरवाही की आग पर फोम डाल दिया जाएगा।



## लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

चल रही पटाखा फैकट्री में लगी आग से हुई तबाही में यह प्रश्न गौण हो गया है कि कितने लोग असमय मौत का शिकार हुए? हरदा ही नहीं, देश के लोगों को यह पूछने का हक कि सालों से यह फैकट्री यो भी बीचर रहवासी क्षेत्र में चल कैसे रही थी? जांच समिति बना ही दी है, जब किसी भी समिति में सरकार ऐसी समिति गठन करने तप्परता दिखाए तो आमजन याद मामलों को लेकर पहले जो जांच समितियाँ गठित की गईं, उनकी फाइलों ने फैसले उगले भी या नहीं! गुना बस हादसे में कलेक्टर, एसपी पराग गाज गिरी थी। आज मुख्यमंत्री हरदाम जा ही रहे हैं... ऐसा ही कुछ निर्णयी

धोने की तपतरा दिखा सकते हैं। हरदा की आग में जिन निर्दोषों की बलि चढ़ गई, उनके परिवारों को न तो फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल और दिनेश को गिरफतारी से संतोष मिलेगा और न ही मुआवजे की राशि उनके आंसू पोछ पाएगी। इसी फैक्ट्री में पहले भी हुए विस्फोट में दो लोगों की जान जा चुकी है। वहाँ के कलेक्टर के आदेश का तत्कालीन (अब इंदौर) सभागायुक्त माल सिंह भायडिया द्वारा भी शत-प्रतिशत पालन के निर्देश दिए गए होते तो फैक्ट्री बंद रहती, ऐसा नहीं हुआ तो दोषी प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण बिना इनती ढील देना संभव ही नहीं प्रप्र में पटाखों, बारूद से विस्फोट की यह में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में हुई भौंते, पेटलावद में 7 दर्जन से अधिक निर्दोषों के चीथड़ों की पोटलियों वाले लोमहर्षक दृश्य और जाच समिति की धोणा लोग भूले नहीं हैं। इससे पहले बालाघाट में 29 और दमोह 7 लोगों की मौत भी ऐसे ही विस्फोट में हो चुकी है। इन सारे विस्फोट के बाद अब यदि लोगों को यह लगने लगें कि 18 वर्ष के बाद बस सीएम बदले हैं... लापरवाही का ढर्ग वैसा ही चल रहा है तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। अब जो होगा, वह भी लोगों को पता है... गुना बस हादसे के बाद जिससे तरह बसों की चैकिंग का अभियान चला था, वैसे ही इंदौर, भोपाल दमोह, बालाघाट, हरदा आदि शहरों

A photograph showing a large pile of debris and rubble in the foreground, with a yellow sign featuring a green logo and Hindi text 'कोटोरंजन' (Kotorenjan) visible in the background.



फैक्ट्री मालिकों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने की सख्ती तो सरकार दिखाएगी ही, लेकिन इन्हें संरक्षण पूर्व मुख्यमंत्री के प्रिय जनप्रतिनिधियों के साथ ही इस सरकार में उसक दिखाने वाले हरदा-बैतूल के जनप्रतिनिधियों से भी मिलता रहा है। सख्त फैसले लेकर खुद को पिछली सरकार से बेहतर दिखाने की कोशिश में लगे डॉ. मोहन यादव को पटाखा फैक्ट्री के संचालकों को संरक्षण देने वाले नेताओं-अधिकारियों के घरों पर भी बुलडोजर चलाने का साहस दिखाना चाहिए। हरदा पटाखा फैक्ट्री को 2022 में कलेक्टर ऋषि गर्ग ने सील करने के आदेश जारी किए थे। सरकार को तत्कालीन संभागयुक्त चाहिए कि ऐसी क्या मजबूरी रही कि इस आदेश के विरुद्ध स्टेप्स दिया ?विस्फोट पीड़ित लोगों के आस्ते बयां कर रहे हैं कि शिकायत करते रहने के बाद भी अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की। ऐसी क्या मजबूरी थी कि ट्रकों से बारूद आता रहा और पुलिस प्रशासन मुस्तैदी दिखाने दिखाने के बजाय मैत्री-भाव दशात रहा और जिला प्रशासन की आंखों पर भी पोलिटिकल प्रेशर की पट्टी बंधी रही। हरदा हादसे का कारण बने प्रशासनिक अधिकारियों पर भी सरकार ऐसी कार्रवाई करे कि बाकी जिलों के अधिकारियों को भी समझा आ जाए कि बदले हुए नियाम में अब ढील-पोल नहीं चलेगी।

# उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विकास की एक नई सुबह

जा. किशन रह्मान-  
(लेखक, भारत सरकार के केन्द्रीय  
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री हैं)

उत्तर-पूर्व क्षेत्र के राज्यों के अनुठे एवं खूबसूरत पहाड़ों व  
द्वीपों में विभिन्न

कहाँ ज्यादा सच हो रहे हैं। व्यापार को आसान बनाया गया है और पर्यटकों के लिए आकर्षण के नए केन्द्रबनाए गए हैं। यह सब बेहतर कनेक्टिविटी के कारण संभव हुआ है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, अपने आप में, अभूतपूर्व राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रेरणादायक समर्पण और प्रत्येक भारतीय के लिए बेहद प्रिय एक लक्ष्य के सामूहिक स्वामित्व की गाथा है और वह लक्ष्य है - भारत के ईशान कोण में प्रगति व विकास की एक नई सुबह की शुरूआत। जैसा कि माननीय गृह मंत्री ने हाल ही में संपन्न एनईसी की 71वीं पूर्ण बैठक के दौरान सही ही कहा है कि पिछला दशक उत्तर-पूर्वी भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय रहा है। इस परिवर्तनकारी घटिकोण ने न केवल इस क्षेत्र में संघर्ष के द्वितीय-प्रशासन के पारंपरिक मॉडल की अवधारणा को तोड़कर शासन के विकास-उन्मुख मॉडल को खड़ा किया है, बल्कि इसके अपेक्षाकृत अधिक एकजुट भारत को बढ़ावा देते हुए सांस्कृतिक और सामाजिक एकीकरण के बीज बोए हैं। हाल ही में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पहली अंतर्राष्ट्रीय रेलवे कनेक्टिविटी, अगरतला-अखोरा रेल लिंक को हरी झंडी दिखाना, इस बात का गौरवपूर्ण उदाहरण है कि कैसे एक समय उपेक्षित रहने वाले भारत का यह सुदूरवर्ती इलाके अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन मानचित्र पर उभर आया है। जीवंत संस्कृतियों और प्रचुर संसाधनों से लैस भारत का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, एक ऐसा इलाका है जिसने काफी लंबे समय तक राजनीतिक उदासीनता का दंशाझे ला रहा है। वास्तविक प्रतिबद्धता की कमी को छुपाने के लिए अक्सर हिंसा और अस्थिरता को एक सुविधाजनक ओट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और ऐसी सिद्धांत एवं व्यवहार के बीच की बड़ी खाइ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती थी।

में प्रधानमंत्री मादी जी के नेतृत्व में किए गए निरंतर प्रयासों से इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में शांति और सुरक्षा का बातावरण बना है। सरकार भौगोलिक और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का डटकर सामना करते हुए विकास एवं समृद्धि के राजमार्ग तयार कर रही है। अरुणाचल के किंबू थो देश के अतिम गांव के बजाय भारत के पहले गांव और राष्ट्रव्यापी वाहबंद विलोज कार्यक्रम के लॉन्च पैड के रूप में पुनर्कल्पित करना उत्तर-पूर्वी क्षेत्र एवं इसके सुदूरवर्ती इलाकों के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। वर्ष 2014 के बाद से 50 से अधिक मंत्रालयों द्वारा क्षेत्रीय विकास में पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ, यह क्षेत्र विकास के अवसरों का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। वर्ष 2014 से, यहां एक वित्तीय क्रांति जारी है, जिसके तहत 54

प्रतिशत की भारी वृद्धि (2014 में 24,819 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023 में 82,690 करोड़ रुपये) या डोनर मंत्रालय के लिए बजट आवान्ट में 152 प्रतिशत की वृद्धि (2014 में 2,332 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023 में 5,892 करोड़ रुपये) की गई है। यह तथ्य एक ऐसे ठोस वित्तीय परिवर्ष की ओर इंगित करता है, जो परिवर्तनकारी एजेंडे को बढ़ावा देता है। हालिया पीएम-डिवाइन योजना, जिसमें विभिन्न राज्यों की जरूरतों के लिए 6,600 करोड़ रुपये की सहायता का वादा किया गया है, इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है। पिछले दशक में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में हासिल की गई प्रगति ने इस क्षेत्र को भारत के एक सुदूरवर्ती इलाके से बदलकर विकास के नए इंजन के रूप में स्थापित कर दिया है। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आई क्रांति ने ऐसे रास्ते खोले हैं जिनपर पहले कभी ध्यान दिया जाता नहीं था।

इस क्षेत्र के पयटन, अर्थव्यवस्था, कृषि-आधारित उद्योग, सेवा क्षेत्र की संभावनाओं एवं युवा श्रमशक्ति प्राकृतिक व जैविक खेती, नवीकरणीय ऊर्जा और दशकों तक अछूते रहे कई अन्य क्षेत्रों का दोहन करके इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के विभिन्न मोर्चों पर एक साथ काम कर रहे हैं। हमने इस क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है तथा अभी कई और उपलब्धियां हासिल करनी हैं। श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने आधी लाइंग जीत ली है। निम्नलिखित पर्कियां भारत के पूर्वोत्तर में एक नई सुबंधन के प्रति हमारी दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प को दर्शाती हैं:

1. निवासियों को अपनी घरेलू वाहनों का उपलब्ध उपलब्धि देना।

2. निवासियों को अपनी घरेलू वाहनों का उपलब्ध उपलब्धि देना।

3. निवासियों को अपनी घरेलू वाहनों का उपलब्ध उपलब्धि देना।

4. निवासियों को अपनी घरेलू वाहनों का उपलब्ध उपलब्धि देना।

5. निवासियों को अपनी घरेलू वाहनों का उपलब्ध उपलब्धि देना।

6. निवासियों को अपनी घरेलू वाहनों का उपलब्ध उपलब्धि देना।

7. निवासियों को अपनी घरेलू वाहनों का उपलब्ध उपलब्धि देना।

8. निवासियों को अपनी घरेलू वाहनों का उपलब्ध उपलब्धि देना।

9. निवासियों को अपनी घरेलू वाहनों का उपलब्ध उपलब्धि देना।

10. निवासियों को अपनी घरेलू वाहनों का उपलब्ध उपलब्धि देना।

## संक्षिप्त खबरें

नगर का विकास पहली  
प्रथमिकातः प्रवीण अग्रवाल

अमरोहा। भारतीय जनता पार्टी की

सदस्यता ग्रहण करने के बाद नगर

पालिकायाक्षय प्रवीण अग्रवाल का

सभासदों एवं समर्थकों ने स्वागत

किया। और तलब के हैं कि बृहदावार को

उन्होंने लखनऊ में डिंडीली सीएम

केशव प्रसाद मोर्य एवं भाजपा प्रदेश

अध्यक्ष भूपेंद्र धौधी की जीजूदूपी में

पार्टी की सदस्यता ली थी।

पालिकायाक्षय ने बताया कि नगर का

विकास ही उनके पहली प्रारम्भिकता

है। प्रधानमंत्री नें दोषी एवं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की

नीतियों से प्राप्त विवाद होकर भाजपा

की सदस्यता अग्रवाल की

ठाकुरी और बृहदावार की गोपनीयता

है। प्रधानमंत्री नें दोषी एवं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की

नीतियों से प्राप्त विवाद होकर भाजपा

की सदस्यता लेने की बात भी कही।

इस दौरान अतुल बंसल, राजू

बादशाह, दुलारीन गिहार, बृहदावार

मध्यसूख गोलंदाज, विजय

शर्मा, मोहित अग्रवाल, विनय

घोटेटिया, देवेश तंत्रवर, अमित

अग्रवाल आदि मौजूद रहे।

ज्ञानवारी मानिला : मुरुलिम पथ

के प्रार्थना पत्र पर 15 फरवरी को

होगी सुनवाई

वाराणसी की जिला अदालत ने

ज्ञानवारी मानिला

परिचय परिसर स्थानित

करने के सुनियन पथ के प्रार्थना

पत्र पर सुनवाई के लिए 15 फरवरी

की तारीख तय की है। हिंदू पक्ष के

अधिकारी मदन मोहन यादव ने

बृहदस्ती तिवार को बताया कि

मुरुलिम पथ व्यापारी की तहस्ताने

में जिला अदालत के हाल के आदेश

पर देवारा शुरू की गयी पाठ-

पाठ को 15 दिन के लिए रोककर

सुनवाई करने का आग्रह किया था।

इस पत्र के लिए दोषी एवं

मानिला की अदालत में

आपातक दर्ज कराने हुए कहा कि जब

उच्च न्यायालय में 12 फरवरी

को इसी मुद्रे पर सुनवाई होनी है तब

निवारी अदालत में हस मामले में

सुनवाई करने का कोई जाइत्य

नहीं है। इस पत्र का लिया जाने

मामले की सुनवाई के लिए 15

फरवरी की तारीख नियत करी।

इंस्टाग्राम पर विषय छात्रों को

दुर्घटना की धमकी

दियी छात्रों से इंस्टाग्राम पर

अश्लीलता करते हुए दुर्घटना की अदालत

में आपातक दर्ज कराने हुए कहा कि जब

उच्च न्यायालय में 12 फरवरी

को इसी मुद्रे पर सुनवाई होनी है तब

निवारी अदालत में हस मामले में

सुनवाई करने का कोई जाइत्य

नहीं है। इस पत्र का लिया जाने

मामले की सुनवाई के लिए 15

फरवरी की तारीख नियत करी।

अंडरामार्गी ने दुर्घटना की

जाइत्य को दुर्घटना की धमकी

दियी छात्रों को देखा जाना चाहिए।

जाइत्य की धमकी देखा जाना चाहिए।

जाइत्य









